JANAAGRAHA CENTRE FOR CITIZENSHIP & DEMOCRACY

प्रेस रिलीज

14 मार्च, 2018, नई दिल्ली

जनाग्रह के भारत की नगरीय-व्यवस्था (ASICS) 2017 के वार्षिक सर्वे का 5वां संस्करण शहरी-व्यवस्थाओं में सुधार को इंगित करता है लेकिन बहुत ही धीमी गति से

बेंगलुरु का गैर-लाभदायी संस्थान **ज**नाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी (जनाग्रह) ने भारत की नगरीय-व्यवस्थाओं के वार्षिक सर्वे की रिपोर्ट के 5वें संस्करण को जारी किया है। शहरों में शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाले इस अध्ययन ने अपने 2017 के संस्करण में पूरे भारत के 20 राज्यों के 23 प्रमुख शहरों को 89 प्रश्नों के आधार पर शामिल किया था. भारत के शहरों का स्कोर 10 में 3.0 और 5.1 के बीच रहा जिसमें ने इस चार्ट में पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष पांच में स्थान पाने वाले शहरों में कोलकाता, तिरुअनंतपुरम, भुवनेश्वर और सूरत हैं जिनका स्कोर 4.6 से 4.5 के बीच रहा. बेंगलुरु, चंडीगढ़, देहरादून, पटना और चेन्नई ने निचले क्रम के पांच शहरों में स्थान पाया है जिनका स्कोर 10 में से 3.0 से 3.3 के बीच रहा।

वैश्विक मानदंड की तुलना में जोहानिसबर्ग, लंदन और न्यूयॉर्क का स्कोर क्रमश: 7.6, 8.8 और 8.8 रहा।

जनाग्रह, पक्षसमर्थन और सुधार के डिप्टी हेड अनिल नायर का कहना है, *"ASICS सड़क और ट्रैफ़िक, कूड़ा, जल, हाउसिंग, सफाई और वायु प्रदूषण जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सेवाओं की गुणवत्ता का मापन नहीं करता बल्कि इसके बजाय स्थानिक नियोजन और डिजाइन मानकों, नगरीय वित्त, नगरीय स्टाफ, शहर स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व और पारदर्शिता तथा नागरिक हिस्सेदारी के "शहरी-व्यवस्थाओं" का मूल्यांकन करके लंबे समय तक चलने वाली उच्च गुणवत्ता के इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को प्रदान करने के लिए शहरों की तत्परता को मापता है"*। 3 से 5.1 की रेंज वाले स्कोर, 23 में से 12 शहर का स्कोर 10 में से 4 से नीचे हैं जो इस तथ्य को दृढ़ता से बताता है कि भारतीय शहर पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है जो कि दीर्घकालिक हो। बार-बार आने वाली बाढ़, कूड़े की विकट समस्या, आग की घटनाएं, इमारत का गिरना, वायु प्रदूषण और डेंगू का फैलना केवल हमारे शहरों की विकट शासन व्यवस्था का संकेत हैं।

"पुणे ने तिरुअनंतपुरम को पीछे छोड़ते हुए ASICS 2017 में पहला स्थान हासिल किया है। सूरत को इस वर्ष की रैंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है।वर्ष 2016 में सूरत 12 स्थान पर था और इस बार 5वां स्थान हासिल किया है। ASICS 2017 के एसोसिएट मैनेजर एवं प्रोजेक्ट लीड विवेक आनंदन नायर का कहना है *यह स्वयं के राजस्व निर्माण, शहर के प्रति व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उच्च व्यय तथा अमृत सुधार पर उन्नत सुधार से पीछे है जिसमें आंतरिक लेखा-परीक्षक और क्रेडिट रेटिंग की नियुक्ति शामिल है"* । भुवनेश्वर ने लगातर सुधार प्रदर्शित किया है और 2016 के 10वें स्थान के पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष छठवें स्थान से चौथे स्थान पर छलांग लगाई है। इस वर्ष सर्वे में जोड़े गए दो नए शहरों, असम का गुवाहटी और आंध्रप्रदेश का विशाखापट्टनम का स्कोर भी उत्साहजनक नहीं रहा और दोनों का स्कोर क्रमश: 3.8 और 3.4 रहा। विशाखापट्टनम और चेन्नई में परिषद के चुनावों में बहुतज्यादा विलंब होने के कारण इन शहरों के स्कोर कम हुआ क्योंकि इससे वार्ड समितियों का गठन, परिषद में लैंगिक प्रतिनिधित्व जैसे पहलुओं पर भी असर पड़ा।

कुल मिलाकर, भारत के शहरों में ASICS के पिछले तीन संस्करणों में कम स्कोर का मिलना जारी है, जिनके प्रदर्शन में 3.4 से 3.9 का बहुत कम सुधार हुआ है। यह शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की धीमी प्रगति को इंगित करता है। जिस गति पर भारत का शहरीकरण हो रहा है और हमारे शहरों में दी जाने वाली जन सेवाओं की खराब स्थिति को देखते हुए यह बहुत ही चिंताजनक है।

यह रिपोर्ट शहरों की व्यवस्थाओं या हमारे शहरों की शासन-व्यवस्था के लिए संस्थागत सुधारों पर तत्काल ध्यान देने पर जोर देती है।

ASICS ने पांच व्यवस्थागत चुनौतियों की पहचान की है जिनका हमारे शहरों के लिए तत्काल समाधान किए जाने की आवश्यकता है ताकि संवहनीय ढंग से नागरिकों के गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान किया जा सके। वे हैं:

1. **सड़क, फुटपाथ, बस स्टॉप जैसी जनोपयोगी तथा जल एवं सीवरेज नेटवर्क जैसी अन्य भूमिगत सेवाओं के मानक डिजाइन तथा शहरों के स्थानिक नियोजन में आधुनिकता, सामयिक संरचना की कमी**
2. **कमजोर वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय संवहनीयता और शहरों की वित्तीय जवाबदेही दोनों के संदर्भों में**
3. **घटिया मानव संसाधान प्रबंधन, स्टाफ की संख्या, कौशल और स्टाफ की सक्षमता, संगठन डिजाइनऔर कार्य-प्रदर्शन प्रबंधन के संदर्भ में**
4. **निशक्त मेयर और नगर परिषद तथा नगर पालिकाओं, अर्ध राजनीतिक एजेंसियों तथा राज्य के विभागों का गंभीर विखंडन**
5. **सुव्यवस्थित नागरिक भागीदारी की पूरी तरह से गैर-मौजूदगी तथा वित्त एवं शहरों के संचालन में पारदर्शिता की कमी**

ASICS रिपोर्ट को नगरीय शासन-व्यवस्था में मुख्य समस्याओं के संबंध में शहर के नेतृत्वकर्ताओं की मदद के लिए डिजाइन किया गया है और यह रिपोर्ट उनके शहर को बेहतर बनाने के लिए संशोधित रोडमैप तैयार करने में मदद करती है

4 नगरीय- व्यवस्थागत घटकों का शहर के आधार पर ASICS स्कोर

शहर	ASICS 2017 स्कोर	ASICS 2017 रैंक	UPD	UCR	ELPR	TAP
पुणे	5.1	1	2.8	7.3	4.9	5.5
कोलकाता	4.6	2	3.7	4.5	6.3	4.0
तिरुअनंतपुरम	4.6	3	2.8	3.5	6.5	5.5
भुवनेश्वर	4.6	4	4.2	4.6	4.7	4.8
सूरत	4.5	5	3.6	5.2	5.5	3.8
दिल्ली	4.4	6	5.1	4.2	5.3	3.0
अहमदाबाद	4.4	7	3.5	5.0	5.6	3.5
हैदराबाद	4.3	8	3.0	5.2	3.3	5.5
मुंबई	4.2	9	2.9	5.9	4.9	3.2
रांची	4.1	10	2.0	3.7	6.0	4.7
रायपुर	4.0	11	2.5	3.7	5.5	4.4
कानपुर	3.9	12	2.7	4.3	4.3	4.2
लखनऊ	3.8	13	2.4	4.1	4.3	4.5
गुवाहटी	3.8	14	2.5	3.5	4.8	4.4
भोपाल	3.7	15	2.3	3.6	4.5	4.2
लुधियाना	3.5	16	3.0	3.0	4.1	3.9
विशाखापट्टनम	3.4	17	2.6	3.8	2.8	4.6
जयपुर	3.4	18	3.4	3.3	4.7	2.1
चेन्नई	3.3	19	2.9	4.0	4.1	2.0
पटना	3.3	20	2.6	3.3	4.8	2.4
देहरादून	3.1	21	2.4	3.3	4.8	1.8
चंडीगढ़	3.1	22	1.8	4.4	3.6	2.5
बेंगलुरु	3.0	23	3.0	3.0	2.9	3.0
लंदन	8.8	-	7.9	9.7	9.4	8.2
न्यूयॉर्क	8.8	-	8.0	9.8	8.8	8.5
जोहानिसबर्ग	7.6	-	5.3	8.8	8.8	7.6

#UPD: नगरीय नियोजन एवं डिजाइन, UCR: नगरीय क्षमताएं और संसाधन, ELPR: सशक्त एवं विधिसम्मत राजनीतिक प्रस्तुति और TAP: पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिभाग ASICS मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त 'नगरीय-व्यवस्था' संरचना के चार घटक हैं

भारत के शहरों की व्यवस्थाओं के वार्षिक सर्वे (ASICS) के बारे में

ASICS हमारे शहरों की शासन-व्यवस्था की गुणवत्ता का उद्देश्यपरक मूल्यांकन है। संपूर्ण चिकित्सा जांच के जैसे, यह नगरी प्रशासन में मौजूद गंभीर व्यवस्थागत खामियों का उल्लेख करता है। ASICS 2017 में पूरे देश के 20 राज्यों के 23 प्रमुख शहरों का मूल्यांकन किया गया है। जनाग्रह की नगरीय-व्यवस्थागत संरचाओं का उपयोग उसे आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए यह सर्वे 89 व्यापक मापदंडों पर पूरे शहरों का मूल्यांकन करता है। ASICS सर्वे में कोई शहर जितना अच्छा प्रदर्शन करता है उसके द्वारा मध्यम एवं लंबे समय तक नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान किए जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है।

प्रत्येक वर्ष, हम कई बार अपने शहर की कई चुनौतियों को अखबारों में सुर्खियां बनते और न्यूज़ टेलीविज़न में प्राइम टाइम पर उन्हें स्थान बनाते हुए देखते हैं। इस तरह की घटनाएं बार-बार होती हैं जैसे हर साल मानसून आता है और अपने साथ जलजमाव, सड़क की टूट-फूट और अंतहीन ट्रैफिक जाम लाता है। मुंबई में कूड़े को जलाने के कारण वायु प्रदूषण, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका वायु प्रदूषण तथा चेन्नई की भीषण बाढ़ जैसी घटनाएं हमें पिछली घटनाओं की याद दिलाती हैं, शायद उसी शहर की। यह दृढ़ रूप से बताता है कि भारत की परंपरागत काम-चलाऊ अवधारण, जिसे 'जुगाड़' के नाम से भी जाना जाता है, इन चुनौतियों को हल नहीं कर पर रही है। हमारे शहर की चुनौतियां इतनी विकट हैं कि हमें इनके लिए रणनीतिक कदम उठानें होंगे। मूल कारण नगरीय शासन व्यवस्थाओं के मूल कारण की पहचान करके उसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है; हमें लक्षणों को ठीक करते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है।

नगरीय शासन पर बल देने वाली व्यवस्थाओं को हम सामूहिक रूप से "नगरीय-व्यवस्थाएं" मानते हैं। "शहरी-व्यवस्थाओं" से आशय कानून, नीतियों, संस्थानों की गुणवत्ता एवं उत्तरदायी प्रक्रिया से है जो हमारे दैनिक जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। 'शहरी-व्यवस्थाएं' परस्पर संबद्ध और एक दूसरे पर आश्रित हैं तथा हमारे शहरों, उनकी चुनौतियों तथा समाधानों की प्रक्रियागत प्रकृति पर जोर देती हैं। नगरीय-व्यवस्थाओं की संरचना में चार अलग लेकिन अंतर-संबंधी घटक होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं:

- नगरीय नियोजन एवं डिजाइन (स्थानिक नियोजन, नगरीय डिजाइन मानक)
- नगरीय क्षमताएं और संसाधन (नगरीय वित्त, नगरीय आधार, IT)
- सशक्त एवं विधिसम्मत राजनीतिक प्रस्तुति (प्राधिकार और कार्य नगरीय परिषद, उनकी यथार्थता) और
- पारदर्शिता, जवाबदेही और हिस्सेदारी (जनसंवाद, सेवा के स्तरों पर जवाबदेही

- ASICS 2017 रिपोर्ट और डेटा बुक यहां से एक्सेस किया जा सकता है: http://www.janaagraha.org/asics/ASICS-2017.html
- डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में डेटा तालिका को यहां एक्सेस किया जा सकता है: http://www.janaagraha.org/asics/ASICS-2017.html
- शहर ASICS मूल्यांकन रिपोर्ट को यहां एक्सेस किया जा सकता है: http://www.janaagraha.org/asics/ASICS-2017.html

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

अनिल नायर| anil.nair@janaagraha.org | 09871916608
विवेक आनंदन नायर| vivek.nair@janaagraha.org | 09740469944

जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी (जनाग्रह) का परिचय

जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी (जनाग्रह) बेंगलुरु का गैर-लाभकीय संस्थान है जो कि जना समूह का हिस्सा है। जनाग्रह का लक्ष्य भारत के शहरों और कस्बों में जीवन की गुणवत्ता में बदलाव लाना है। यह जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है क्यों कि इसमें मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता तथा नागरिकता की गुणवत्ता शामिल है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जनाग्रह नगरीय-व्यवस्थाओं में सुधार के लिए शहर के आसपास के लोगों तथा सरकारों के साथ शहर में सक्रिय नागरिकता बढ़ाने के लिए नागरिकों के साथ कार्य करता है। आप जनाग्रह के बारे में www.janaagraha.org पर और अधिक पढ़ सकते हैं।

जन अर्बन स्पेस फाउंडेशन (जन USP) का परिचय

जन अर्बन स्पेस एक प्रोफेशनल सर्विसेज सोशल इंटरप्राइज (PSSE) है जो रूपांतरण करता है, भारत के शहरों के स्थानिक आयाम पर विश्वस्तरीय कार्य करता है। जन USP में चार अंतर-अनुशासनात्मक स्टूडियो - नगरीय नियोजन स्टूडियो; नगरीय डिजाइन स्टूडियो; स्थानिक मैपिंग और और विश्लेषणात्मक स्टूडियो; तथा शिल्प एवं डिजाइन स्टूडियो होते हैं। शहर की स्थानिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई स्टूडियो ने जनUSP की व्यवस्थागत अवधारणा को प्रतिबंबित किया है। जन अर्बन स्पेस गैर-लाभदायी निकाय है। आपजन USP के बारे में www.jusp.org पर और अधिक पढ़ सकते हैं